

इंदौर, मंगलवार 21 अप्रैल 2026

वर्ष : 5 अंक : 149  
पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

dainikindoresanket.com

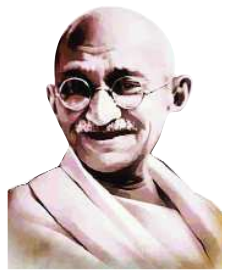
dainikindoresanket

dainikindoresanket

dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

# इंदौर संकेत



राष्ट्रपिताको नमन...

मर्यादा टूटे तो लोकतंत्र  
भी घायल होता है

अक्षय की बात  
अपनों के साथ

लोकतंत्र की असली ताकत उसके संस्थानों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि अपनी भाषा, व्यवहार और आचरण से मर्यादा की सीमाएं तोड़ने लगें, तो यह केवल व्यक्तिगत चूक नहीं रहती—यह लोकतंत्र की साख पर सीधा आघात बन जाती है। हालिया विवादों के केंद्र में रहे प्रीतम लोधी का आचरण इसी गंभीर सवाल को सामने लाता है।

राजनीति में तीखापन नया नहीं है, लेकिन गिरावट नई है। मतभेद लोकतंत्र की आत्मा हैं, मगर अपमान और आक्रामकता उसकी हत्या कर देते हैं। जब एक विधायक सार्वजनिक मंचों पर संयम खोता है, तो वह केवल विरोधियों को नहीं, बल्कि उस जनता को भी संदेश देता है जिसने उसे चुना है—कि जिम्मेदारी से ज्यादा अहम उसका अहंकार है।

जनप्रतिनिधि का हर शब्द एक मिसाल बनता है। गांव की चौपाल से लेकर शहर के मंच तक लोग उसी भाषा को अपनाते हैं जो उनके नेता बोलते हैं। ऐसे में अगर संवाद की जगह कटाक्ष, तर्क की जगह तकरार और मर्यादा की जगह मनमानी दिखे, तो समाज में भी वही संस्कृति पनपती है। यह केवल राजनीति का पतन नहीं, सामाजिक संवाद का भी अवमूल्यन है।

भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े और अनुशासित संगठन के लिए यह स्थिति और भी असहज है। सवाल उठता है—क्या पार्टी केवल चुनावी जीत तक सीमित है, या अपने प्रतिनिधियों के आचरण की जवाबदेही भी तय करेगी? अनुशासन का दावा तभी सार्थक होता है, जब वह व्यवहार में भी दिखे।

आज का दौर पारदर्शिता का है। सोशल मीडिया हर नेता को आईने के सामने खड़ा कर देता है। ऐसे में मर्यादाहीन व्यवहार छिपता नहीं, बल्कि और तेजी से फैलता है। परिणामस्वरूप जनता के मन में अविश्वास गहराने लगता है—और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऐसी घटनाएं अब अपवाद नहीं रहें, बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही हैं। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा, तो आने वाले समय में राजनीति केवल शोर और टकराव का मंच बनकर रह जाएगी, जहां न नीति बचेगी, न नैतिकता।

अंत में सवाल सीधा है—क्या जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास के योग्य आचरण कर रहे हैं, या फिर अपने ही व्यवहार से उस विश्वास को तोड़ रहे हैं? क्योंकि जब मर्यादा टूटती है, तो केवल छवि नहीं, लोकतंत्र भी घायल होता है।

न्यूज ब्रीफ

- बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का आज दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से हींगी मुलाकात
- लखनऊ: टैरर फांडिंग पर एटीएस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी बैंक से जुड़े 8 बैंक खाते सीज
- यूपी में 'आधी आबादी' के हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट, सीएम योगी करेंगे अगुवाई
- यूपीएस: मेक्सिको में एक कनाडाई महिला की गोली मारकर हत्या, पांच अन्य घायल
- लखनऊ: पिता ने 16 साल की बेटी की ली जान, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम
- 'धमकियों के बीच अमेरिका के साथ बातचीत मंजूर नहीं', ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ बोले



इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक हलकों में लंबे समय से जारी अटकलों के बीच अब एक नया नाम तेजी से उभरकर सामने आया है। अब तक जहां कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में थे, वहीं विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव के विशेष समीकरणों और संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी की अनुशंसा के चलते पूर्व नगर भाजपा महामंत्री कमलेश

शर्मा का नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

अंदरखाने की राजनीति तेज

सूत्र बताते हैं कि इंदौर विकास प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा के भीतर खासी रस्साकशी चल रही है। कई वरिष्ठ नेता और वर्तमान पदाधिकारी इस पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम निर्णय संगठन और सरकार के संतुलन के आधार पर लिया जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में

संघ की भूमिका निर्णायक बनती दिख रही है।

संघ की अनुशंसा का बड़ा महत्व

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुरेश सोनी की राय हमेशा संगठनात्मक नियुक्तियों में प्रभावी रही है। यदि उनका समर्थन किसी नाम के साथ जुड़ता है, तो वह नाम स्वाभाविक रूप से मजबूत दावेदार बन जाता है। कमलेश शर्मा के नाम को इसी नजरिए से देखा जा रहा है।

## IDA की कुर्सी पर शर्मा सरप्राइज

संघ और सीएम के वीटो से बदले समीकरण

मुख्यमंत्री की पसंद भी अहम

मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्तमान में प्रदेश संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में वे ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहते हैं जो संगठन में स्वीकार्य होने के साथ-साथ प्रशासनिक कामकाज में भी संतुलन बनाए रख सकें। सूत्रों के अनुसार जिस तरह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हरिनारायण यादव का तय बताया गया उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। वैसे भी हरिनारायण यादव कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक माने जाते हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ मंत्री कैलाश के बीच किस तरह से अंदरूनी खटपट चल रही है यह किसी से छुपा नहीं है।

मेंदोला फैक्टर भी प्रभावी

कमलेश शर्मा को इंदौर के

कदावर नेता रमेश मेंदोला का करीबी समर्थक माना जाता है। मेंदोला का इंदौर की राजनीति में मजबूत प्रभाव है और उनके समर्थन से किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि यह समीकरण सही बैठता है तो कमलेश शर्मा की राह काफी आसान हो सकती है।

अन्य दावेदारों की उम्मीदें बरकरार

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और कई अन्य नाम भी दौड़ में बने हुए हैं। पार्टी नेतृत्व अंतिम समय तक सभी पहलुओं पर विचार कर सकता है। लेकिन जिस तेजी से कमलेश शर्मा का नाम उभरा है, उसने बाकी दावेदारों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं।

पुराने अनुभव का लाभ

कमलेश शर्मा पहले नगर भाजपा महामंत्री रह चुके हैं और संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं, जो उन्हें अन्य दावेदारों के मुकाबले बढत दिला सकता है। आईडीए जैसे संस्थान में संगठनात्मक समझ रखने वाला व्यक्ति सरकार की योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से उतार सकता है।

जल्द हो सकता है फैसला

सूत्रों के मुताबिक इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद को लेकर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि संगठन और सरकार किस चेहरे पर भरोसा जताते हैं। फिलहाल, इंदौर की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और हर दिन बदलते समीकरण इस पद को और भी दिलचस्प बना रहे हैं।

## डेली कॉलेज परिसर में बीजेपी का आयोजन, दिगी उतरे मैदान में



इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • डेली कॉलेज बोर्ड के संरक्षक और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बोर्ड प्रेसिडेंट को चार पन्नों का तीखा पत्र लिखा है। इसमें कॉलेज परिसर में बार-बार हो रहे राजनीतिक आयोजनों पर गहरी आपत्ति जताई है। खासकर यहां हो रहे बीजेपी, संघ और उनसे जुड़े संगठनों के आयोजनों पर आपत्ति ली है। पत्र में लिखा है कि संस्थान के परिसर, नाम और प्रतिष्ठा का उपयोग बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उनसे जुड़े संगठनों के कार्यक्रमों के लिए किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक

है। इससे संस्थान की निष्पक्षता, गरिमा एवं स्वतंत्र पहचान को गंभीर क्षति पहुंची है। इसकी 140 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा भी है। ऐसी संस्था को किसी भी प्रकार के राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रमों का मंच बनाना पूरी तरह अनुचित है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि हाल के समय में कई अहसरों पर कॉलेज परिसर राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ दिखाई दिया है। इससे यह धारणा बन रही है कि संस्थान को एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा है। सिंह ने सितंबर 2025,

बोर्ड से की दिगी ने यह मांग

दिग्विजय ने कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मांग की है कि वे तत्काल स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दी गई। क्या स्वीकृति प्रदान की गई तथा क्या इस संबंध में कोई नीति मौजूद है। साथ ही, उन्होंने यह भी पूछा है कि हाल के वर्षों में ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एवं संबन्धित प्राधिकरणों से मांग की है कि वे तुरंत एक स्पष्ट नीति जारी करें, जिसमें कॉलेज परिसर को किसी भी राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध हो।

4 अक्टूबर 2025, 1 फरवरी 2026 तथा 22 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं अब एक चिंताजनक पैटर्न का रूप ले चुकी हैं।

ग्रीन फील्ड रोड के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू

## बदलेगी इंदौर के 20 गांवों की किस्मत



इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • इंदौर-उज्जैन के बीच बनने वाली ग्रीन फील्ड सड़क का काम धरातल पर दिखने लगा है। जिले के 662 किसानों को 626 करोड़ से अधिक मुआवजा वितरण करने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सांवेर तहसील में अब तक 95 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों के खाते में डाला जा चुका है। वहीं राजस्व अमले ने रतनखेडी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इंदौर के 20

और उज्जैन जिले के आठ गांवों से गुजरने वाली 48 किमी लंबी सड़क के लिए 313.839 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें 292.523 हेक्टेयर भूमि निजी है और 21.326 हेक्टेयर भूमि शासकीय है।

इंदौर के पितृ पर्वत के पास से उज्जैन तक बनने वाली चार लेन ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण सिंहस्थ से पहले किया जाना है। सड़क भू-अर्जन के लिए 484.140 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी,

अब 'नॉन-एक्सेस कंट्रोल' होगी सड़क

ग्रीन फील्ड सड़क हाइट पर बनाने के साथ सर्विस रोड भी बनाई जानी थी, लेकिन विरोध के बाद एक्सेस कंट्रोल से नॉन-एक्सेस कंट्रोल के रूप में निर्माण करने का अनुमोदन किया। यानी सड़क जमीन की ऊंचाई पर बनाई जाएगी। इससे सड़क के दोनों तरफ सात-सात मीटर चौड़ी 77 किमी लंबी सड़क नहीं बनाई जाएगी। जमीन के बराबर सड़क होने से ग्रामीण और किसान कहीं से भी सड़क पर आना-जाना कर सकेंगे। आसपास की खेती की जमीन में पानी जमा होने की परेशानी भी नहीं होगी।

लेकिन किसानों के विरोध के कारण अधिक मुआवजा देने के लिए बिक्री छॉट (सेल डीड एनॉलिसिस) की प्रक्रिया अपनाई गई।

## स्वच्छता की खुमारी के बीच बेहाली के दौर में इंदौर

लगातार गिर रहा जल का स्तर  
दोहन के मामले में सबसे अचल



इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • इंदौर में रोजाना बोरिंग करवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की चेतावनियों के बावजूद शहर में प्रतिदिन 20 से 25 नए बोरिंग किए जा रहे हैं। नर्मदा जल की गुणवत्ता को लेकर घटते भरोसे और भागीरथपुरा जैसी घटनाओं के बाद लोग अब अपने निजी जल स्रोत पर निर्भर होना चाहते हैं। वहीं प्रशासन ने अप्रैल बीतने के बावजूद अवैध बोरिंग और मशीनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई सख्त दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

जनवरी में भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद लोगों में सुरक्षित पानी को लेकर चिंता बढ़ी है। यही कारण है कि शहर में बोरिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। बोरिंग एजेंसियों के अनुसार, आउटर एरिया-बायपास, सुपर कार्रिडोर और स्कू-12 जैसे क्षेत्रों में लगातार बुकिंग मिल रही है, जबकि शहर

73% क्षेत्र 'अति-दोहन' की श्रेणी में

रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर जिले में भूजल दोहन का स्तर 117% तक पहुंच गया है, यानी जितना पानी जमीन में रिचार्ज हो रहा है, उससे कहीं अधिक निकाला जा रहा है। जिले का 73 फीसदी हिस्सा 'अति-दोहन' की श्रेणी में आ चुका है और विशेषज्ञों का कहना है कि अब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं बचा है। शहरी क्षेत्र की स्थिति भी 'क्रिटिकल' हो चुकी है।

के अंदर इंतजार और ज्यादा करना पड़ रहा है। वर्तमान में घरेलू बोरिंग की दर 140 से 150 रुपये प्रति फीट है, जबकि अनुभवी के नाम पर अतिरिक्त राशि भी ली जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, जिले में भूजल का रिचार्ज मुख्यतः बारिश पर निर्भर है, लेकिन रिचार्ज के साधन बेहद सीमित हैं।

शादी-ब्याह ने बढ़ाया एलपीजी का संकट, जुगाड़ पर सिलेंडर



इंदौर में एक बार फिर से

एलपीजी का संकट बढ़ गया है। इसके पीछे अक्षय तृतीया के बाद लगातार शादियों के मुहूर्त हैं। शादियों में सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है। जिन लोगों को एक से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, उन्हें दिक्कत आ रही है। 25 और 26 अप्रैल को होगी डिमांड : हालांकि इंदौर में पहले की तरह सिलेंडर की दिक्कत नहीं है, लेकिन शादियों की वजह से दबाव बढ़ गया है। जिन लोगों को एक से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इधर 25 और 26 अप्रैल को मुहूर्त होने के कारण सैकड़ों शादियां तय हैं। कार्ड का हवाला देकर मांग रहे सिलेंडर : शहर में हलवाईयों ने गैस सिलेंडर की व्यवस्था की जिम्मेदारी वर और वधु पक्ष पर डाल दी है। कलेक्टर कार्यालय के खाद्य विभाग में भी सिलेंडरों की मांग को लेकर 100 से ज्यादा आवेदन आए हैं, लेकिन अधिकारी लोगों को गैस

लोग शादी का हवाला देकर सिलेंडर मांग रहे हैं

इतना ही नहीं, लोगों ने मेन्यू में कटौती करने के साथ ही मेहमानों की सूची भी छोटी कर दी है। दूसरी तरफ शादी वालों को कैटसर्स सिलेंडर मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे 2 से ढाई हजार रुपए प्रति सिलेंडर वसूल रहे हैं। ऐसे में शादी वाले घरों में दिक्कत हो रही है। दरअसल, अक्षय तृतीया के बाद इंदौर में लगातार शादियों के मुहूर्त हैं। जिससे एलपीजी सिलेंडरों की मांग बढ़ गई है।

एजेंसियों से संपर्क करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी ओर, गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तरों में लोग शादी के कार्ड दिखाकर सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। कई लोगों के घरों में 25 और 26 अप्रैल को शादी है और रसोई के लिए किसी को 8 तो किसी को 10 सिलेंडर चाहिए। लेकिन इतने सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं।

चालानी कार्रवाई और वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त ट्रैफिक पुलिस



इंदौर में सबसे गंभीर ट्रैफिक

की समस्याओं को लेकर विविध जनहित याचिकाएं हैं। इस पर लगातार हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। आखिरकार लगातार मॉनिटरिंग के चलते बीआरटीएस कार्रिडोर पूरी तरह से हटा गया है और सभी बस स्टॉप हटा दिए गए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच को यह जानकारी अधिकारियों ने दी। सुनवाई में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बागडिया ने सवाल उठाया कि जब वीवीआईपी, वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। बाद में ट्रैफिक जवान वीवीआईपी निकलते ही गायब हो जाते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक डीसीपी से पूछा कि किन लोगों को जीरो ट्रैफिक की सुविधा है। इस पर बताया गया कि

ट्रैफिक सिपाही कोने में खड़े होते हैं

वरिष्ठ अधिकार अजय बागडिया ने कहा कि ट्रैफिक को लेकर हाईकोर्ट के पुराने आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ट्रैफिक सिपाही चौराहों पर नहीं खड़े हैं और कोने में खड़े होकर चालान बनाने में अधिक जोर होता है। अभी भी 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल्स चालू नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट बेंच ने भी कहा कि वह यू टर्न लेकर हाईकोर्ट की ओर आते हैं तो ट्रैफिक सिपाही नहीं दिखते हैं।

ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल सुरक्षा कारणों से ही ट्रैफिक ब्लिंक करने की सुविधा करते हैं, वह भी एक मिनट के लिए। वहीं इंदौर हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन व वरिष्ठ अधिकारिता विनय चेलावत ने कहा कि इंदौर में अभी स्वीकृत ट्रैफिक पुलिस बल की तुलना में 237 का बल कम है।

## न्यूज ब्रीफ

शहर हुआ भाजपा मय, प्रमुख चौराहों को भाजपा ध्वज से सजाया गया

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए इंदौर के चौराहों को भाजपा ध्वजों से सजाया गया है। डेली कॉलेज के मुख्य द्वार से मेन हॉल तक भाजपा ध्वज और होर्डिंग्स से सजाया गया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के सभी प्रमुख चौराहों की साज सज्जा भाजपा ध्वज से की गई है। एयरपोर्ट से लेकर डेली कॉलेज, रेलवे स्टेशन से लेकर डेली कॉलेज, राऊ बायपास, रिंग रोड के सभी चौराहों को भाजपा ध्वजों से सजाया गया है।

एनाएचआरसी विशेष प्रतिवेदक की बैठक सम्पन्न, मानवाधिकार मुद्दों की समीक्षा

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के विशेष प्रतिवेदक श्री सुभाष चन्द्रा के इंदौर दौरे के दौरान आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सीमा कनेश सहित वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभागों महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक पवन सिंह चौहान तथा शैलेन्द्र सौलंकी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त नरेंद्र भिड़े, नगर निगम आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विशेष प्रतिवेदक सुभाष चन्द्रा ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सामुदायिक वन अधिकार, जनजातीय वर्ग के कल्याण और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई।

# जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन पर ही लूट का लगा आरोप, 5 पुलिसकर्मी हुए सरपैंड

## इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • इंदौर की खाकी पर एक और बड़ा दाग लगा है। डीसीपी जॉन 2 कुमार प्रतीक ने एक दिन पहले ही लसुडिया थाने के एक एसआई व चार पुलिसकर्मीयों को निलंबित कर लाइन अटेंच किया था। अब सामने आया है कि इन पर वारंट तामीली के लिए गुंडागर्दी करने के साथ ही घर से 22.50 तोला सोना भी गायब करने का भी शक है। गंभीर आरोपों के चलते यह सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। लसुडिया थाने के एसआई संजय विश्णोई के साथ ही प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा, प्रणित भदौरिया, रवींद्र कुशवाह, दिनेश

गुर्जर और दीपेंद्र मिश्रा पर कार्रवाई हुई है।

यह हुई घटना-मामला इंदौर के हरिदर्शन अपार्टमेंट में रहने वाले गौरव जैन से जुड़ा है। रिटायर्ड सीएसपी राकेश गुप्ता की शिकायत पर इनके खिलाफ ग्वालियर जिला कोर्ट से चेक बाउंस केस में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। दोनों के बीच 65 लाख के लेन-देन का विवाद है। आरोप है कि एक अप्रैल की रात 11:45 बजे एसआई संजय विश्णोई के साथ यह पुलिसकर्मी तामीली के लिए गौरव के फ्लैट पहुंचे थे। सीसीटीवी कैमरे तोड़े, घर में घुसे-परिजनों का आरोप है कि घर



में घुसने के दौरान पहले फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। फिर नकली चाबी से ताला खोलकर पुलिसकर्मी घर में घुसे और घर की तलाशी ली। आरोप है कि इसी दबिश के दौरान जैन की पत्नी के 22.50 तोला

सोने के जेवर गायब कर दिए गए। साथ ही चांदी के सिक्के, घड़ियां, मोबाइल व अन्य दस्तावेज भी लिए गए। ऑनलाइन रिश्वत भी ली-इसके साथ ही गौरव ने प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा पर 27 हजार रुपए

## लूट की धारा में केस दर्ज हो

फरियादी गौरव जैन ने बताया कि इसमें लिखित शिकायत मैंने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को की है। मेरी मांग यह है कि मेरे घर पर लूट हुई है, मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया है, मेरे घर से सोना गायब हुआ है। चांदी के सिक्के, मोबाइल और घड़ियां भी गई हैं। इसमें संबंधित पुलिसकर्मीयों पर जो धाराएं बनती हैं, उनमें केस दर्ज होना चाहिए। मुझे मेरा सोना दिलाया जाए। रिटायर्ड सीएसपी राकेश गुप्ता पर भी कार्रवाई हो। लगातार गुंडे भेजकर और पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिसकर्मीयों को भेजकर परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है।

रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाए हैं। गौरव अपने वकील से संपर्क करना चाहता था। सूत्रों के लिए आरक्षक शर्मा ने 10 हजार रुपए दोस्त के खाते में और 17 हजार रुपए अपने बेटे के खाते में गौरव से लिए।

गौरव को थाने में न रखते हुए पास के गेस्ट हाउस में रखा और आरोप है कि वहां भी रिटायर्ड सीएसपी राकेश गुप्ता के दो साथियों से पिटाया। शर्मा के खिलाफ भी जांच बैट गई है।

## देपालपुर नगर में रोज होता ट्रैफिक जाम

अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं निकाल पाए कोई समाधान

जिलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर • दैनिक इंदौर संकेत देपालपुर नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या कोई नई बात नहीं नगर में रोज लंबा जाम लगता है। घंटों वाहन स्कूल बस इस जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले का समाधान आज तक नहीं निकाल पाए, मीटिंग हुई नियम बने ट्रैफिक जाम पर बातें हुई लेकिन जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो समाधान आज तक नहीं निकला सड़क किनारे बड़े-बड़े वाहन खड़े होते हैं। ठेला गाड़ी सड़क किनारे लगी रहती है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पहले भी कहीं बार ट्रैफिक जाम को लेकर अखबारों में खबरें प्रकाशित हुईं लेकिन अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगी देपालपुर एसडीएम रहे रवि वर्मा ने पहले ट्रैफिक जाम को लेकर जनपद पंचायत में मीटिंग बुलाई थी। नगर परिषद के अधिकारी से



लेकर पुलिस विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मीटिंग में मौजूद थे। बातें हुई चालानी कार्रवाई होगी फुटकर दुकानों को जगह अलग से देंगे कोई भी दुकानदार सड़क किनारे दुकान नहीं लगाएगा लेकिन वह बातें जनपद पंचायत के उस मीटिंग हॉल तक ही सीमित रह गई आज तक न तो किसी जनप्रतिनिधि ने इस विषय पर बात की न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने सबसे बड़ी बात इसी

रोड पर तहसील कार्यालय, लोकसेवा केंद्र, जनपद पंचायत, सेशन कोर्ट, शासकीय अस्पताल, तमाम सरकारी ऑफिस मौजूद है। सुबह से लेकर शाम तक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इसी रोड से निकलते हैं कई बार एम्बुलेंस पुलिस वाहन भी जाम में फंस जाते हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं निकाल पाए। रोज-रोज लगता ट्रैफिक जाम से नगर की जनता में आक्रोश है। आखिर कब तक

देपालपुर में जाम लगता रहेगा एक तरफ तो नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात करते हैं। लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या पर कोई बात नहीं करना चाहता क्या जनता से किए गए वादे खोखले साबित हो रहे हैं या फिर सड़क किनारे लगी इन दुकानों से किराया वसूली का मामला चल रहा है।

देपालपुर नगर परिषद से आम जनता को कार्यवाही की उम्मीद सबसे पहले सड़क किनारे रखे बोर्ड बैनर को हटाया जाए सड़क किनारे लग रही दुकानों को कहीं और जगह दी जाए। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाए तभी नगर की आम जनता को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकता है। पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित करें एक-एक पुलिस जवान को ट्रैफिक समस्या के लिए चौकस पर तैनात करें जिससे नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान मिल सके।

## इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ा

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद पश्चिम मप्र विशेषकर इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वालों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है। घरलू छतों के अलावा दफ्तरों, कारखाने, दुकानों की छतों पर भी पैनलस लगाकर बिजली तैयार की जा रही है। इंदौर महानगरीय क्षेत्र में सुपर कॉरिडोर, बायपास पर बसाहट के साथ जुलाई 25 में 18500 स्थानों पर सोलर संयंत्र थे, ये दिसंबर में 22000 हो गए, वर्तमान स्थिति में 27000 से ज्यादा स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इंदौर के बाद दूसरा स्थान उज्जैन जिले का है, उज्जैन जिले में पिछले वर्ष जुलाई की स्थिति में 3450 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन था, जो दिसंबर में 4250 और अब 5800 स्थानों पर सोलर संयंत्र लगने के साथ बिजली उत्पादन जारी है। रतलाम जिले में जुलाई में 18500 स्थानों पर पैनलस लगे थे,



जो दिसंबर में 2660 और अब 4555 हो गए हैं। वहीं देवास जिले में जुलाई में 2250, दिसंबर में 2750 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा था, जो अब 3700 स्थानों पर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली तैयार की जा रही है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि रूफ टॉप सोलर नेट मीटर को लेकर कंपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करती है, आए गए प्रकरण तत्काल मंजूर किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को सस्मिडी समय पर दिलाने के प्रत्येक कार्य तेजी से किए जाते हैं।

## खंडेलवाल म्यूजिकल ग्रुप द्वारा तृतीय साधना सत्र शनिवार 18 अप्रैल को सम्पन्न



## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक मुरली खण्डेलवाल द्वारा प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना से किया गया। साधना सत्र की शुरुआत श्रीमती सीमा कूलवाल द्वारा आशा के भजन \*तोरा मन दर्पण कहलाए से की गई, और विशेष प्रस्तुति मधुसूदन खंडेलवाल (मधु मुकेश) द्वारा एकल और युगल गीत की दी गई। अन्य सदस्य शरद खण्डेलवाल (बम्ब), पंकज सेठी, सुशील साकुनिया, बालकृष्ण कूलवाल, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, अशोक खण्डेलवाल, सुशील खण्डेलवाल जितेन्द्र खंडेलवाल, प्रदीप रावत, मयंक साकुनिया, विष्णु कूलवाल, नरेंद्र ओढ़, श्रीमती मंजू खंडेलवाल श्रीमती सुनीता खंडेलवाल, श्रीमती शोषी खण्डेलवाल, यशी खंडेलवाल आदि के द्वारा आशा, लता, रफी, मुकेश, किशोर, हेमंत कुमार के गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के सूत्रधार शरद खण्डेलवाल थे। अंत में सभी सदस्यों के सामूहिक गायन द्वारा प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी गई।

## क्षेत्रीय कार्यशाला कल, मेहमान कार्यकर्ताओं का आना शुरु

स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत



## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • रेलवे स्टेशन पर भाजपा नगर द्वारा 3 जगह काउन्टर लगाए गए हैं। सियागंज, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और नेहरू पार्क के सामने, काउन्टर टेबल पर महिला कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर एवं आरती उतारकर अतिथियों का अंगवस्त्र पहनाकर व गुलाब की कलियां देकर स्वागत किया गया। वहीं उनके चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गयी है। उन्हें लालदंत मंजन, पेस्ट, ब्रश, साबुन और दातुन के साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं की कीट भी दी गई है। वाहनों से उन्हें होटल छोड़ा गया। क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे नगर प्रभारी राजेश सिंह सोलंकी की स्टेशन पर विधायक रमेश मंदोला, सुधीर कोल्हे, सुरेश कुतवाड़े, रोहित चौधरी, मनोज मिश्रा, गजानन गावड़े, रजत शर्मा, आदित्य पांडे, श्रीकांत दुबे, पृथ्वी गारे, आशीष शर्मा, रितेश वीरंग, चंद्रभान सिंह सोलंकी, यशवंत शर्मा, संतोष सिंह, दुष्यंत वर्मा, ऋषभ गुर्जर, भावना बारगल, गीता राठौर, दीपा श्रीवास्तव, नीतू सिंह रेणु स्वामी कृष्णा वेदी ने अगवानी की।

## पासी समाज का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न



## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • अखिल भारतीय पासी समाज इंदौर व पासी समाज सामूहिक विवाह समिति इंदौर द्वारा पासी मांगलिक भवन विनोबा नगर इंदौर में 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। विवाह गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य संजय शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर पासी समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं व खिलाड़ियों का सम्मान किया, साथ समाज की अन्य प्रतिभाओं व वरिष्ठ समाजसेवियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अतिथिगण क्षेत्र क्र. 5 के विधायक मेहेंद्र हार्डिया, म.प्र. महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रीना बौरासी सेतिया, क्षेत्रीय पार्षद राजेश उदावत, म.प्र. पासी समाज के अध्यक्ष गोविन्द बावरीया, दिलीप शर्मा, पूर्व पार्षद, परसराम वर्मा पूर्व पार्षद, राधे बौरासी पूर्व पार्षद, नन्दु बौरासी पूर्व एल्डरमेन थे। अतिथियों का स्वागत परसराम वर्मा, धीरज बौरासी, दिलीप बौरासी, विजय वर्मा, गोविन्द कैथवास, महेश वर्मा आदि ने किया।

## नए जिन मंदिर का मध्य शिलान्यास समारोह 23 को

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • खंडवा रोड स्थित लिंबोदी में श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भव्य भूमि शिलान्यास महोत्सव 23 अप्रैल गुरुवार को प्रातः 8 बजे से श्री कृष्ण एवेन्यू फेस 3 में आयोजित होगा। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दहू ने बताया कि यह आयोजन श्रमण संस्कृति के महामहिम पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं सान्निध्य प्रदाता परम पूज्य श्रुत संवेगी मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज, मुनि श्री अग्रिमित सागर जी, मुनि श्री सहज तैयार जी एवं शुल्लक श्री 105 श्रेयस सागर जी महाराज संसद के पावन सान्निध्य में एवं प्रतिष्ठाघार पीपूष भैया जी के निर्देशन में विधि विधान के साथ सम्पन्न होगा। मंदिर के लिए भूमिप्रदाता मनीष बंसल, अनुरोधकर्ता मा. सुशील -जयंत कासलीवाल एवं इंजीनियर मा. विकास पाटोदी का विशेष योगदान प्राप्त है।

## किफायती फूड ऐप 'टोइंग' अब इंदौर में उपलब्ध

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • किफायती फूड डिलीवरी ऐप टोइंग ने आज इंदौर में अपने लॉन्च की घोषणा की। पिछले 7+ महीनों में, टोइंग ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारत के 24 शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज की है और यह अपने-पैपर पर खाने-पीने की सभी चीजों पर सबसे कम कीमत की गारंटी देता है, जो रेस्टोरेंट के टेबल मेन्यू की कीमत के बराबर या उससे कम होती है। इसके अलावा, टोइंग पर किए गए किसी भी ऑर्डर पर न तो पैकेजिंग चार्ज लिया जाता है और न ही कोई प्लेटफॉर्म फीस। इससे टोइंग बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती फूड डिलीवरी ऐप बन जाता है। यूजर्स इस ऐप पर बिरयानी, बर्गर और बाउल जैसे कई तरह के व्यंजन 99 रुपये से कम में ऑर्डर कर सकते हैं। टोइंग, जिसे 2025 के सेकंड हाफ में पुणे से लॉन्च किया गया था, अब आगरा, वडोदरा, गुवाहाटी, नासिक, नागपुर, पटना, औरंगाबाद, भोपाल, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भी लाइव है।

## चौड़ी सड़क के लिए आगे आए रहवासी, चलाए हथोड़े

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • नगर निगम द्वारा जंजीरवाला से लेकर अटल द्वार तक बनाई जाने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क के लिए पिछले दिनों निशान और नपती के साथ-साथ रहवासियों को नोटिस दिए गए थे। फुटपाथ की चौड़ाई कम करने की मांग को लेकर रहवासी मेयर से भी मिले, लेकिन कोई हल नहीं निकला तो रहवासियों ने खुद अपने स्तर पर बाधाएं हटाना शुरू कर दीं। नगर निगम शहर के कई स्थानों पर प्रमुख मार्गों की सड़कों को बनाने की तैयारी में है और इसके लिए बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किए गए हैं। दबा बाजार से जगन्नाथ धर्मशाला तक छवानी की सड़क, जिंसी से लक्ष्मीबाई प्रतिमा, कंडीलपुरा से किला मैदान और चंदननगर से कालानी नगर तक की सड़क बनाने का काम तेजी से शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर नोटिसों की कार्यवाही पूरी की जा रही है। निगम ने कई स्थानों पर नोटिस जारी कर दिए हैं और साथ ही सुनवाई भी हो रही है। इसी बीच निगम ने जंजीरवाला चौराहे से लेकर नेहरू नगर होते हुए अटल द्वार तक बनने वाली



60 फीट चौड़ी सड़क के लिए पिछले दिनों नपती और निशान लगाने की कार्रवाई की थी और बाधक निर्माणों पर लाल निशान लगाए गए। इसके बाद रहवासी वहां दोनों ओर से फुटपाथों की चौड़ाई कम करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया के साथ महापौर पुष्पमित्र भार्गव से मिलने पहुंचे थे और फुटपाथ की चौड़ाई कम कराए जाने की मांग की थी, ताकि उनके घर बच सकें, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते रहवासियों ने खुद मोर्चा संभाला और बाधक निर्माण हटाना शुरू कर दिए हैं। सड़क के दोनों किनारों पर तोड़ रहे हैं पांच-पांच फीट के हिस्से-

पिछले दो दिनों से नेहरू नगर और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में रहवासी खुद अपने परिजनों के साथ मिलकर बाधक निर्माणों के हिस्से हटा रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि मकान, दुकान और ओटलों के पांच-पांच फीट के हिस्से तोड़ रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों ने वहां निरीक्षण के दौरान रहवासियों को खुद बाधाएं हटाने को कहा था। उक्त सड़क बनने से वाहन चालक सीधे जंजीरवाला चौराहे से एमआईसी थाने के सामने अटल द्वार तक पहुंच सकेंगे और अब तक उन्हें मालवा मिल, पाटनीपुर अथवा एबी रोड से लेकर एमआईसी तक जाना पड़ता है।

## डाक विभाग में डायरेक्ट एजेंट्स के चयन हेतु साक्षात्कार 20 मई को

## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग द्वारा सम्पूर्ण इंदौर जिले में करने हेतु डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं के व्यवसाय अर्जन के लिए डायरेक्ट एजेंट्स का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु साक्षात्कार का आयोजन 20 मई को एमजी रोड स्थित श्री कृष्णा टाकीज के पास मुख्य डाकघर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर संभाग प्रवर अधीक्षक डाकघर से प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक ईसेंटिव एवं कमीशन के आधार पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होना आवश्यक है तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान एवं स्थानीय भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रवर अधीक्षक डाकघर, इंदौर नगर संभाग, एमजी रोड स्थित इंदौर नगर मुख्य डाकघर की तृतीय मंजिल, श्री कृष्णा टाकीज के पास उपस्थित हो सकते हैं।

## जिला फुनाकोशी ओपन करार चैपियनशिप में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन



## दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • रविवार को नेहरा स्टेडियम में आयोजित जिला फुनाकोशी ओपन करार चैपियनशिप में सत्य साई विद्या विहार स्कूल के कक्षा 7 'इ' के छात्र जयवीर जेटवा ने 12 वर्ष तक के आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं, एकायना स्कूल के कक्षा 5 के छात्र धैर्य सोलंकी ने 9 वर्ष तक के आयु वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह सफलता सुश्री दिलजीत कौर और सुशीला सर के निर्देशन में संभव हो सकी। साथ ही, इस उपलब्धि के लिए सेंसई अशोक सेन सर और सेम्पाई का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन भी सराहनीय रहा।

न्यूज बीफ

**नीनादेवी अग्रवाल की स्मृति में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में 6700 से अधिक अग्रवाल बंधु पहुंचे**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति, बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन एवं हेल्थ फॉर भारत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमती नीनादेवी अग्रवाल की पुण्य स्मृति में चलाए जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के अंतर्गत छठे स्वास्थ्य परीक्षण एवं निशुल्क जांच शिविर का आयोजन एयरपोर्ट रोड स्थित बाबाश्री रिसोर्ट पर सम्पन्न हुआ जिसमें दूसरे दिन 541 समाज बंधुओं ने शामिल होकर अपनी विभिन्न प्रकार की 32 जांचे कराईं। इसके पूर्व पहले दिन 560 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। इस तरह कुल 1101 समाज बंधुओं ने इस शिविर में पहुंचकर मधुमेह एवं मोटापे से मुक्ति के अभियान का पहला चरण पार कर लिया। अब तक आयोजित हुए छः शिविरों में कुल मिलाकर 6701 लोगों ने अपनी प्रारम्भिक जांचे कराई हैं। अगला शिविर 25-26 अप्रैल को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक गीता भवन प्रांगण में आयोजित होगा।

**अग्रवाल सांस्कृतिक मंच नंदानगर ने किया साईं मंदिर में अनूठा आयोजन**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • श्री अग्रवाल सांस्कृतिक मंच नंदानगर की ओर से अक्षय तृतीया पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सोमवार को राज्य के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का तुलादान कर उनके वजन के बराबर शिक्षण सामग्री (स्टेशनरी) का वितरण क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों के बीच किया गया। संस्था के प्रमुख सोनू अग्रवाल, अजय मित्तल, सत्यप्रकाश अग्रवाल पुर विधायक रमेश मेंदोला, समाजसेवी गणेश गौयल, विजय मित्तल एवं जगदीश बाबाश्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तुलादान के पश्चात विजयवर्गीय के आतिथ्य में नंदा नगर साईं मंदिर स्थित गौशाला में गौपुत्र एवं गौसेवा के अनुष्ठान में राकेश अग्रवाल, कमलेश सिंघल सहित मंच के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और विजयवर्गीय का आत्मीय स्वागत किया।

**3 हजार खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेता 27 अप्रैल को कारोबार बंद रखकर प्रदर्शन करेंगे**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • इंदौर-उज्जैन संभाग के बीज एवं कीटनाशक तथा कृषि आदान विक्रेता सोमवार 27 अप्रैल को आल इंडिया इनपुट डीलर एसोसिएशन एवं जारूक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर के आह्वान पर अपना कारोबार बंद रखकर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कलेक्टर, कमिश्नर को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन भेंट करेंगे। प्रदेश के करीब 3 हजार और इंदौर-उज्जैन संभाग के करीब एक हजार व्यापारी इस आन्दोलन में शामिल होंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, इंदौर जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण दुबे, सचिव जितेन्द्र जैन एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी ने बताया कि खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार का कई बार ध्यानाकर्षण करने के बाद भी अब तक कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया है। इसके विरोध में महाराष्ट्र राज्य संगठन ने 27 अप्रैल से बेमुह्त बंद का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में देश के सभी राज्यों के कृषि आदान विक्रेता पहले चरण में 27 अप्रैल को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे।

## वाँशिंग सेंटरों में नर्मदा और बोरिंग का पानी नहीं होगा उपयोग

**जलसंकट और भूजल स्तर में गिरावट होने पर लिया निर्णय**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • नगर निगम ने नर्मदा और बोरिंग के पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त निर्णय लिया है, जिसके तहत इंदौर के वाँशिंग सेंटरों में नर्मदा और बोरिंग के पानी से गाड़ियां धोने और अन्य कामों में उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके पीछे इंदौर में जलसंकट और भूजल में गिरावट होना है। शहर में 500 से 700 फीट तक भूजल स्तर पहुंच गया है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने इसके लिए आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावशाली रहेगा।

**पानी की बर्बादी पर लगाम**

निगम आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में शहर में पानी की कमी है। जलसंकट की स्थिति और अधिक गंभीर नहीं हो इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की बर्बादी होती है उसको रोकना है। इसके लिए शहर के वाँशिंग सेंटरों पर नर्मदा और बोरिंग के पानी का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ शहर में होने वाले निर्माण कार्यों में भी बोरिंग और नर्मदा का पानी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही ट्रीटेड पानी का उपयोग करना होगा। नगर निगम ने 35 स्थानों पर ट्रीटेड पानी की व्यवस्था की है। इसके लिए हाईडेट बनाए गए हैं। शहर के आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।



**35 हाईडेट की लोकेशन कहां, जानकारी नहीं?**

वाँशिंग सेंटर संचालक दिनेश काले ने बताया कि हम नगर निगम के प्रतिबंध का पालन करेंगे, लेकिन हमें पानी की वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। निगम ने 35 स्थान पर हाईडेट से ट्रीटेड पानी लेने की बात कही, लेकिन ये कहां बनाए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। पानी निःशुल्क होना चाहिए। टैंकर का किराया मांगा जा रहा है।

**पाइप लाइन से ट्रीटेड पानी देने की योजना नहीं हुई सफल**

निगम ने साल 2023 में पूर्व निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा भी बोरिंग और नर्मदा का पानी वाँशिंग सेंटरों में प्रतिबंध करने पर विचार किया था, लेकिन प्रतिबंधित नहीं किया गया था। निगम द्वारा वाँशिंग सेंटरों को एसटीपी का ट्रीटेड पानी देने की योजना बनाई थी, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। इसके साथ ही पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने शहर में चल रहे आरओ प्लांट में होने वाली पानी बर्बादी को लेकर सवाल उठाए थे। जब आरओ प्लांट में पानी साफ किया जाता है, तो बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है, इस पानी का रियूज किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

## पानी बचाना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

**'जल गंगा संवर्धन अभियान' से प्रदेश में जल संरक्षण को मिली नई गति**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाया जा रहा है। पानी बचाना बेहद जरूरी है। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के इस अनमोल वरदान से कभी भी कमी महसूस नहीं करें। इसके लिए हमें अपने वर्तमान जल स्रोतों के साथ सख्त चुके जल स्रोतों को संरक्षित करना ही होगा। उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार और समाज के साझा प्रयासों से हो रहे इस अभियान में बीते एक माह में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। प्रदेश में संचालित 'जल गंगा संवर्धन अभियान' ने अल्प समय में ही उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। विगत 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ यह अभियान जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन और जनभागीदारी का एक व्यापक जन-आंदोलन बनता जा

रहा है। इस अभियान के प्रभाव से ही मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग सुधारकर अब तीसरे स्थान पर आ गया है। अभियान से पहले मध्यप्रदेश नेशनल रैंकिंग में छठवें स्थान पर था। राज्य सरकार द्वारा आगामी 30 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान में 16 विभागों की 58 गतिविधियां नियत की गई हैं। इसके लिए लगभग 6 हजार 278 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान में कुल 2 लाख 44 हजार से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को चिन्हित कर लगभग 6 हजार 236 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आयुक्त, मनरेगा ने बताया कि अभियान की एक ही प्लेटफॉर्म पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक एकीकृत डैश बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे सभी विभाग अपनी-अपनी विभागीय गतिविधियों की प्रगति दर्ज कर रहे हैं। इस डैश बोर्ड से जिलेवार रैंकिंग भी सुनिश्चित की जा रही है। इस डैश बोर्ड से प्रशासनिक एवं विभागीय पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिल रहा है।

**फिरोजिया ट्रॉफी विजेताओं के लिये अतिरिक्त पुरस्कार की घोषणा की**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में खेल सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। शासन का प्रयास है कि खिलाड़ियों को हर स्तर पर आधुनिक खेल संरचना, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। शासन के इन प्रयासों से मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभाएं विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उज्जैन में भी विभिन्न खेल मैदानों में खेल व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उज्जैन के क्षीर सागर मैदान को भी नगर निगम और खेल विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को देर रात उज्जैन में फिरोजिया ट्रॉफी का फाइनल मैच देखा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने इस अवसर पर फिरोजिया ट्रॉफी की विजेता टीम को रूपए 1 लाख और उप विजेता टीम को 51 हजार रूपए के अतिरिक्त नगद पुरस्कार की घोषणा भी की।

**'लव यू जिन्दगी' में आज लाल परी थीम पर सजेगी महफ़िल**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • महिला प्रकोष्ठ अग्रवाल समाज के 'लव यू जिन्दगी' कार्यक्रम के सातवें सत्र का शुभारम्भ मंगलवार 21 अप्रैल को होटल सयाजी पर होगा। इस दौरान करीब 150 वे सखियां अनूठे अंदाज में अपना परिचय प्रस्तुत करेंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना पंजीयन करा रखा है। प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल एवं आयोजन से जुड़ी मोनिका, तिलोत्तमा, मीना और वैशाली ने बताया कि यह एक ऐसी दावत होगी जिसमें नई शामिल हुई सखियों को कुछ मस्तीभरे अंदाज में अन्य सखियों के समक्ष स्वयं को रू-बरू कर अपना परिचय देना होगा। कार्यक्रम में सखियों से लाल परी की थीम पर सज-धजकर आने का आग्रह किया गया है। पार्टी में डोजे और तम्बोला भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लाल परी थीम का चयन इसलिए भी किया गया है कि पृथ्वी और हृदय, दोनों से ही लाल रंग का गहरा रिश्ता बना हुआ है इसलिए इस बात लाल परी की थीम रखी गई है। लव यू जिन्दगी को भावना के अनुरूप इस महफ़िल में भी मौज मस्ती और मनोरंजन के तमाम कार्यक्रम शामिल रहेंगे।

**ऐतिहासिक अभिलेखों के सहारे मुस्लिम पक्ष ने ख़ा दावा, हाईकोर्ट में रखे दस्तावेज**

**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • धार भोजशाला परिसर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने अपने विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए। मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट अशरफ वारसी ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, सरकारी अभिलेखों और गजट सूचनाओं के आधार पर अपना पक्ष रखा। एडवोकेट वारसी ने दलील दी कि वर्ष 1904 से पहले तक इस परिसर पर मुस्लिम समुदाय का सतत और अनुपातिक कब्जा रहा है। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड, गजट नोटिफिकेशन और पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन अभिलेखों में स्थल को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से 1935 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि उसमें इस स्थल को मस्जिद माना गया है और

अन्य गतिविधियों की अनुमति न देने का उल्लेख स्पष्ट रूप से दर्ज है। मुस्लिम पक्ष ने कुरान, हदीस और अन्य धार्मिक दस्तावेजों के साथ सरकारी अभिलेखों के आधार पर अपने दावे दोहराए। मुस्लिम पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने इस मामले को जनहित याचिका की तरह प्रस्तुत किया है, जबकि यह विवाद सिविल प्रकृति का है और इसे सक्षम सिविल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। सुनवाई में अभी इंटरवींस की दलीलें अभी शेष हैं। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सलमान खुशींद अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। वहीं सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से भी सीनियर एडवोकेट सुनील जैन ने अपने तथ्य रखे, लेकिन समायाभाव के कारण उनकी दलील अधूरी रह गई, जिस पर सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी।

**परशुराम जयंती पर विश्व हिंदू परिषद- बजरंग दल ने किया श्रद्धालुओं का स्वागत**



**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • परशुराम जयंती के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा शहर में भव्य मंच सजाकर श्रद्धालुओं एवं समाजजनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह जानकारी विहिप-बजरंग दल के प्रचार प्रमुख अन्नू गेहलोत द्वारा दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। आयोजन में बड़ी संख्या

में समाज के लोग एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से ओत-प्रोत रहा। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष संदीप जोशी का विशेष सम्मान करते हुए उन्हें प्रतीक स्वरूप तलवार भेंट की गई, जिसे परंपरा, सम्मान और गौरव का प्रतीक बताया गया। कार्यक्रम में पार्षद मनोज मिश्रा सहित उपस्थित अतिथियों का तिलक एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।

**सुनील कुमार चौधरी महारत्न इंदौर अलंकरण 2026 से सम्मानित**



**दैनिक इंदौर संकेत**

इंदौर • कवि कला, और कलाकार कल्याण कोष का आयोजन हिंदी साहित्य समिति इंदौर में 19 अप्रैल को विभिन्न विधाओं शिक्षा चिकित्सा विधि समाज सेवा रक्षा खेल अभिनव कवि संगीत कला तथा अन्य विधियों अन्य वीडियो में 111 विद्वान विदुषी और विशिष्ट विभूतियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक और समाजसेवी सुनील कुमार चौधरी का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि योगेंद्र महंत पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रवेश के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा अनिवार्य होगी। आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, जन्म अंक सूची की छायाप्रति भी संलग्न भेजना होगा।

प्रयोग कर दूरस्थ क्षेत्र में छात्र प्रतिशत विद्यार्थी की उपस्थिति शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम और दूर्यशन प्रथा पर नियंत्रण तथा अंतरराष्ट्रीय गायत्री परिवार में संभाग में संस्था की महत्वपूर्ण भागीदारी का विशेष प्रयास कर सफलता अर्जित किया। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक जितेंद्र शिवहर एलन पुरोहित एडवोकेट कचरानी योगदान रहा। शिव चौधरी के सम्मान प्राप्त होने पर प्रकाश मानवत सतीश बैरागी, दिनेश दुबे, जितेंद्र यादव, आशीष शिंदे, कमल सोनी, मानिक मालवी, एहसान अली तथा समाजसेवी का रेणुका चंदेल वी वैशाली शिंदे ने हार्दिक बधाई प्रेषित की है। विधि की है कि पूर्व में भी चौधरी को कई सम्मानों से नवाजा गया है। कार्यक्रम का सफल संचालन राहुल मिश्रा तथा आभार दिनेश शर्मा एडवोकेट द्वारा किया गया।

सांध्य दैनिक

# इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापटी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बड़ाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश निःशुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

**कार्यालय का पता**

5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर, गुरुद्वारे के सामने, इंदौर

**संपर्क: 94250-64357, 94245-83000**

**सम्पादकीय**

**रफतार पर भारी पड़ती मौत की राह**

देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल दो फीसदी राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौत की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब तीस फीसदी तक पहुंच गई है। इसमें दोराय नहीं कि देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार बेहद जरूरी होता है। आम लोगों के लिए जीवनरेखा मानी जाने वाली सड़कों का निर्माण भी इसी श्रेणी में आता है। देश में पिछले कुछ वर्षों में नई सड़कें बनाने की गति निश्चित रूप से तेज हुई है, लेकिन इसके साथ ही हादसों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। विशेषकर उच्च तकनीक की मदद से तैयार किए जा रहे एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग चमकदार एवं सुविधाजनक जरूर दिखते हैं, मगर ये सुरक्षित सफर की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल दो फीसदी राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौत की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब तीस फीसदी तक पहुंच गई है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शीघ्र अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक सुस्ती या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण एक्सप्रेस-वे एवं गलियारा नहीं बनने चाहिए। गौरतलब है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के सरकार के दावों के बावजूद इनमें साल दर साल बढ़ोतरी ही रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में देश में 4.56 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें लगभग 1.59 लाख लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2020 के कोरोनाकाल में पूर्णबंदी के कारण सड़क हादसों में कुछ कमी आई, लेकिन उसके बाद वर्ष 2021 में करीब 4.2 लाख, 2022 में 4.61 लाख और 2023 में 4.80 लाख दुर्घटनाएं हुईं। यानी पांच वर्षों में 21 लाख से ज्यादा सड़क हादसों में करीब आठ लाख लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन इसमें कमी लाने के प्रयास सरकारी कागजों से बाहर निकलकर धरातल पर प्रभावी रूप से अमल में आते नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर जिन खतरों को टाला जा सकता है, अगर उनकी वजह से लोगों की जान जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से नागरिकों की सुरक्षा में व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।

**सड़क पर दौड़ती नामर्दगी, इंदौर की सड़कों पर शॉर्टकट नहीं, श्मशान का रास्ता ढूंढ रहे हैं ये 'रॉन्ग साइड नामर्द'**



बेखौफ भागती मौत! गलत दिशा में दौड़ते ये वाहन सिर्फ ट्रैफिक नहीं तोड़ रहे, बल्कि श्मशान की बुकिंग करा रहे हैं। याद रखें, अंत या तो अस्पताल का सफेद बिस्तर होगा या चिता की राख।

इंदौर नंबर वन है, पर किसमें? सफाई में तो हम चमक गए, लेकिन सड़क पर उतरते ही हमारा 'संस्कार' डूबने में बह जाता है। आज इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, मौत का नग्न नाच चल रहा है। नियम तोड़ना अब गलती नहीं, बल्कि एक घटिया किस्म का 'स्वैग' बन चुका है। रॉन्ग साइड से गाड़ी घुसाना बहादुरी नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की चिता सजाने की बेशर्मा तैयारी है।

**कुछ सेकंड की 'चालाकी', उम्र भर की 'खामोशी'**— हर चौराहे पर कुछ ऐसे जल्दबाज जांबाज दिख जायेंगे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा कीमती दो सेकंड का पेट्रोल लगता है। यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानसिक दिवालियापन है। जब आप रॉन्ग साइड गाड़ी डालते हैं, तो आप रास्ता नहीं काटते, आप किसी हंसते-खेलते परिवार की गर्दन पर मौत की आरी चलाते हैं। आपकी यह 'स्मार्टनेस' किसी मां की गोद उजाड़ सकती है और किसी बच्चे के सिर से पिता का साया छीन सकती है।

**दबाई या कायरा?**— सड़क पर दिखाई जाने वाली यह हेकड़ी दरअसल मानसिक बीमारी है। नियम मानना अगर जिम्मेदारी है, तो नियम तोड़ना एक ऐसा सामाजिक अपराध है जिसकी सजा सिर्फ चालान नहीं, बल्कि सफेद कफन है। याद रखिए, आप सड़क के राजा नहीं, बल्कि उस 'यमराज' के एजेंट हैं जो किसी भी वक्त किसी बेगुनाह को उठा सकता है।

**ट्रैफिक एक्सपर्ट की सीधी चेतावनी:** यह तो 'मंडर' है!— ट्रैफिक विशेषज्ञ राजकुमार जैन का साफ कहना है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग कोई हादसा नहीं, बल्कि एक

'सुनियोजित हमला' है।

> 'सामने से आने वाला व्यक्ति उस दिशा से खतरे के लिए तैयार ही नहीं होता। यह अचानक हुआ प्रहार है, जिसमें बचने की गुंजाइश शून्य होती है। यह एक्सीडेंट नहीं, सीधा विनाश है।'

**हमारा मौन बढ़ा रहा इन 'सड़क छाप गुंडों' का हौसला-** पुलिस को कोसना बंद कीजिए। असली समस्या हमारी चुपची है। हम गलत को देखते हैं, पर टोकते नहीं। हमारी यही खामोशी इन 'रॉन्ग साइड योद्धाओं' को बेलगाम बना रही है। जिस दिन समाज ने इन 'सड़क के लुटेरों' को आड़ना दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन मौत का यह खेल बंद हो जाएगा।

**कड़वा सच: आईने में खुद को देखिए-** अहंकार बनाम जान रॉन्ग साइड चलना मर्दानगी नहीं, सोच का कचरा है। व्यवस्था का कत्ल एक गलत मोड़ पूरी शहर की रफतार का गला घोट देता है। निर्दोष की बलि सजा अक्सर उसे मिलती है जो नियम मान रहा था।

**अंतिम चेतावनी: फैसला आपका है!**— अगर हम खुद को 'सभ्य' कहते हैं, तो यह सभ्यता सड़क पर क्यों दम तोड़ देती है? आज तय कर लीजिए: या तो नियमों के साथ सम्मान से चिए, या फिर उस खामोश मातम का हिस्सा बनने को तैयार रहें जिसकी अगली हेडलाइन में नाम आपका या आपके किसी अपने का हो सकता है।

लेखक - राजकुमार जैन, स्तंभकार

**प्रसंगवश - 21 अप्रैल: राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस**

**जब व्यवस्था बोलती है, तो नाम सिविल सेवकों का होता है**

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस उस अदृश्य शक्ति का उत्सव है जो देश को शासन व्यवस्था को गति, स्थिरता और दिशा प्रदान करती है। 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिन उन सिविल सेवकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो केवल प्रशासनिक पदों पर नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी योजनाओं को नीति-पत्रों से निकालकर समाज की वास्तविक जरूरतों से जोड़ते हैं और विकास को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाते हैं। संकट की घड़ी हो या विकास की चुनौती, उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और निष्ठा पूरे राष्ट्र को संतुलन और विश्वास देती है। यह अवसर हमें उनके मौन लेकिन प्रभावशाली योगदान को समझने और एक ऐसे प्रशासन के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है, जो अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और जनकेंद्रित हो।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का ऐतिहासिक आधार उतना ही प्रेरक है जितना इसका वर्तमान संदेश। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेट्रकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के प्रथम बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने उन्हें 'देश का स्टील फ्रेम' (स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया) कहा, जो एक मजबूत, निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासन को राष्ट्र निर्माण में अनिवार्य भूमिका को दर्शाता है। उनका यह संदेश सिविल सेवकों के लिए निर्भीकता, निष्पक्षता और जनसेवा की स्पष्ट दिशा बन गया। यह दिवस उसी विचार को जीवंत करता है, जब प्रशासनिक सेवाओं के महत्व को पुनः स्मरण करते हुए उनके योगदान को सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लिया जाता है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का उद्देश्य सिविल सेवकों के योगदान को सम्मान देना ही नहीं, बल्कि उन्हें जनसेवा में अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देना है। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा उच्च कार्य करने वाले अधिकारियों/जिलों/संगठनों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सफल क्रियाव्यवस्था का सम्मान है। यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत को मान्यता देता है, बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र में बेहतर कार्य की प्रेरणा भी पैदा करता है। साथ ही यह दिन पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-केंद्रित शासन को मजबूत करने का संदेश देता है, ताकि सरकारी योजनाएँ बिना बाधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें।

भारत जैसे देश में, जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता अत्यधिक है, सिविल सेवकों की भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवनरेखा के समान है। वे नीतियों को लागू करने वाले साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव के वास्तविक रक्षक हैं। विकास योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, वंचित और कमजोर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा समाज को एकता के सूत्र में

बाँधना—ये सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर होती हैं। संकट के समय उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे कोविड-19 जैसी महामारी हो, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हों या कोई अन्य राष्ट्रीय संकट, सिविल सेवक सदैव अग्रिम पंक्ति में रहकर देश को संभालते हैं। उनकी अदृष्ट निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यपरायणता ही भारत को हर कठिन परिस्थिति में स्थिरता और प्रगति की दिशा प्रदान करती है।

आज का समय तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल नवाचार का युग है, जिसने सिविल सेवकों की जिम्मेदारियों को पहले से अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। अब उन्हें पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर शासन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना होता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने ई-गवर्नेंस को मजबूत किया है, जिससे ऑनलाइन सेवाएँ, डिजिटल लेन-देन और सरल प्रक्रियाएँ जनता तक सुविधाजनक रूप से पहुँच रही हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल जगुरुकता जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। ऐसे में सिविल सेवकों का दायित्व है कि वे इन चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रशासन को अधिक सक्षम, जन-केंद्रित और भविष्य उन्मुख बनाएँ, ताकि भारत एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ सके।

आज सिविल सेवकों के सामने सामाजिक-आर्थिक असमानता, पंचांगीय संकट और जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनके लिए दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान जरूरी हैं। इनसे निपटने के लिए नवाचार, सहयोग और दूरदर्शी सोच अपनाना आवश्यक है। आदर्श सिविल सेवक वही है जो निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ जनहित को सर्वोपरि रखे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस इस विचार को मजबूत करता है और प्रशासन में सुधार, दक्षता और पारदर्शिता पर चिंतन का अवसर देता है। निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और मजबूत व्यवस्था से सिविल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासन वास्तव में जनता के हित में कार्य करे।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सिविल सेवकों के लिए आत्मचिंतन और कर्तव्यनिष्ठा को पुनः जागृत करने का प्रेरक अवसर है। यह दिवस सिविल सेवकों के उस विचार को फिर से सशक्त करता है, जिसमें उन्होंने निष्पक्षता, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही को सुशासन की आधारशिला बताया था। इस अवसर पर सिविल सेवकों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे देश, संविधान और नागरिकों के हित में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनकी यह निष्ठा ही भारत को मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में आधार बनती है। यह दिवस उनके योगदान को सम्मान देने के साथ यह विश्वास भी जगाता है कि सिविल सेवाएँ ही राष्ट्र की एकता और विकास की वास्तविक शक्ति हैं।

**कृति आरके जैन, सृजनिका, बड़वानी (मप्र)**

**आंचलिक**

**प्याज 7 से 13 रुपए किलो बिका, लागत नहीं मिलने से किसानों ने की समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग**



**दैनिक इंदौर संकेत**

**खरगोन** • प्याज के दाम गिरकर 7 से 13 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। लागत मूल्य की नहीं मिलने से किसानों का असंतोख से प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जिले में बारिश और ठंड के मौसम में लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की रोपाई की जाती है। यहां प्रति हेक्टेयर औसतन 25 टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है। खरगोन जिले में 50 से अधिक प्याज भंडार गृह भी मौजूद हैं। किसान सुरेश कुशवाहा ने बताया कि प्याज की फसल पर प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए की लागत आती है। वर्तमान में इंदौर मंडी में

**महिला आरक्षण कानून बना, कांग्रेस ने पूछा लागू क्यों नहीं?**

**दैनिक इंदौर संकेत**

**धार** • जिला महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून लागू करने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीती महेश्वरी ने भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।

महेश्वरी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने की पक्षधर रही है और पार्टी ने उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने भाजपा के इस प्रचार को गलत बताया कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुका है। इसके बावजूद, उन्होंने यह बड़ा सवाल उठाया कि कानून बनने के बाद भी इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया और महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ कब तक मिलेगा।

महिला आरक्षण कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इसे लागू करने की प्रक्रिया को अगली जगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि नई जनगणना के आधार पर



सीटों का पुनर्निर्धारण होने के बाद ही यह आरक्षण प्रभावी हो सकेगा। प्रीती महेश्वरी ने कहा कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए इस प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है।

उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को केवल चुनावी मुद्दा बनाया उचित नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक राजनीतिक भागीदारी देना आवश्यक है ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भूमिका निभा सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने और सरकार से इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

**ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर: प्रवेश के लिए चौड़ा कर रहे शुक्रदेव मुनि द्वार**



**दैनिक इंदौर संकेत**

**खंडवा** • ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान प्रवेश में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इस लिए मंदिर के शुक्रदेव मुनि द्वार को तोड़कर चौड़ा किया जा रहा है। वहीं मंदिर के पीछे की ओर जुना महल को तोड़कर तिरुपति मंदिर की तर्ज पर 5 हजार भक्तों की क्षमता वाला वेंटिंग एरिया बनाया जाएगा। जिसकी जमीन को समतल किया जा रहा है।

**स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस रिसाव, पानी में तैर रहे दो बच्चों की हालत बिगड़ी**

**दैनिक इंदौर संकेत**

**धार** • शहर के जिस स्विमिंग पूल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बताया जाता है, वहीं सोमवार रात करीब 8 बजे एक गंभीर लापरवाही सामने आई। पूल में क्लोरीन गैस के पाइप से अचानक रिसाव शुरू हो गया। उस समय कई बच्चे पानी में तैराकी कर रहे थे, जिन्हें गैस फैलते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे पानी के भीतर ही छटपटाने लगे।

स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद परिजनों और कोच ने तुरंत बच्चों को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान बसंत विहार कॉलोनी की 4 वर्षीय प्रकृति और 7 वर्षीय हर्षित की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। दोनों बच्चों को तत्काल प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया।

**24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा**

डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को खतरे से बाहर बताया, लेकिन एहतियातन उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि

**पद महिलाओं के पास, फैसले ले रहे पति, खंडवा में पनपा 'डबल कुर्सी' कल्चर**

**दैनिक इंदौर संकेत**

**खंडवा** • देश में 33% महिला आरक्षण पर चल रही चर्चाओं के बीच खंडवा जिले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 50% से अधिक है। जिले में 11 प्रमुख राजनीतिक पदों पर महिलाएं काबिज हैं, जबकि 7 पदों पर पुरुष हैं। इसके बावजूद सरकारी दफ्तरों में 'डबल कुर्सी कल्चर' पनप गया है, जहां एक कुर्सी महिला जनप्रतिनिधि की और दूसरी उनके पति की होती है। वर्तमान में स्थिति यह है कि पद पर महिलाएं बैठी हैं, लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक फैसले पदों के पीछे से उनके पति ही ले रहे हैं।

जिले की सियासत में महिलाएं भले ही भागीदारी कर रही हैं, लेकिन पदों के आगे और पीछे उनके पति ही पूरी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। खंडवा विधायक कंचन तनवरे के पति मुकेश तनवरे को लोग 'सुपर विधायक' बोलते हैं। सारे कार्यक्रम वही तय करते हैं। वहीं, खंडवा महापौर अमृता यादव के पति अमर यादव ने सांसद



## न्यूज़ ब्रीफ

30 करोड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त, 12 मकान हटाए गए

### दैनिक इंदौर संकेत

**इंदौर** • इंदौर जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेशकीमती शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में प्रशासनिक अमले द्वारा ग्राम खजराना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने बताया कि शासकीय सीलिंग की भूमि, खसरा क्रमांक 442/1, क्षेत्रफल लगभग 30,000 वर्गफीट पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान यहां निर्मित कुल 12 मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई।

आरटीओ द्वारा स्ट्रेज कैरिज परमिट पर संचालित 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों पर कार्यवाही

### दैनिक इंदौर संकेत

**इंदौर** • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा स्ट्रेज कैरिज परमिट पर संचालित पुरानी यात्री बसों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बताया गया कि वर्ष 2025 में स्ट्रेज कैरिज परमिट पर संचालित वर्ष 2010 एवं उससे पूर्व के मॉडल की यात्री बसों के संबंध में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 136 वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित समयवाधि में वाहनों का प्रतिस्थापन नहीं किए जाने के कारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इंदौर संभाग द्वारा उनके स्थायी परमिट निरस्त कर दिए गए तथा संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा वाहन की आयु की गणना पंजीयन दिनांक से किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसी क्रम में विगत 02 जनवरी 2026 को वर्ष 2011 मॉडल की 136 बसों के स्वामियों को उनके स्थायी परमिट पर नवीन (अवतन) मॉडल के वाहनों का प्रतिस्थापन कराने हेतु नोटिस जारी किए गए।

# सांदीपनी स्कूल प्रवेश नीति : आसपास के सरकारी स्कूलों पर ताला!

आरटीओ गुट्टा : 9425064357

### इंदौर • दैनिक इंदौर संकेत

सांदीपनी स्कूलों में प्रवेश को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आरोप है कि लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक सुनियोजित रणनीति के तहत केवल आसपास के सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही सांदीपनी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। इस कदम के पीछे दूरगामी योजना होने की चर्चा शिक्षा जगत में जोर पकड़ रही है।

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों की इस नीति का मकसद सांदीपनी स्कूलों के आसपास स्थित हाई स्कूल और कम छात्र संख्या वाले मिडिल स्कूलों को धीरे-धीरे खत्म करना है। जैसे-जैसे इन स्कूलों से छात्रों का रुझान कम होगा, उन्हें बंद करने का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके बाद इन स्कूलों की जमीन और इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग अन्य सरकारी योजनाओं या परियोजनाओं में किए जाने की संभावना जताई जा रही है।



शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यह नीति न केवल छोटे स्कूलों के अस्तित्व पर खतरा है, बल्कि ग्रामीण और गरीब तबके के छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच भी सीमित कर सकती है। कई अभिभावकों में भी इसको लेकर असंतोष देखा जा रहा है।

**राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी** -सबसे बड़ा

सवाल यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर इंदौर का राजनीतिक नेतृत्व अब तक चुप क्यों है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की खामोशी पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे 'शिक्षा व्यवस्था के केंद्रीकरण की साजिश' करार दिया है, लेकिन अब तक कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया है।

## आरटीई की भावना पर सवाल

सांदीपनी स्कूलों में प्रवेश को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी और संवैधानिक बहस का रूप ले लिया है। शिक्षा जगत के जानकारों का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय की मौजूदा रणनीति सीधे तौर पर 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' की मूल भावना के खिलाफ जाती नजर आ रही है।

दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि हर बच्चे को उसके निवास स्थान के पास ही स्कूल की सुविधा मिले। इस अधिनियम की मंशा यह रही है कि बच्चों को दूर जाने की मजबूरी न हो और हर 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आरोप है कि डीपीआई की योजना के तहत आसपास के सरकारी स्कूलों के बच्चों को व्यवस्थित तरीके से सांदीपनी स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे नजदीकी हाई स्कूल और कम छात्र संख्या वाले मिडिल स्कूल धीरे-धीरे खाली हो सकते हैं, जिससे उनके बंद होने की आशंका बढ़ रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्थानीय स्कूल खत्म होते हैं, तो यह न केवल आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, बल्कि कमजोर और ग्रामीण वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच भी प्रभावित होगी। दूर स्थित स्कूलों तक पहुंचना उनके लिए एक नई बाधा बन सकता है।

# राज्य शासन के आदेश को उन्हीं के अधिकारी ने दी चुनौती, कोर्ट से मिला स्टे

## मामला प्रदेश राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया की नियुक्ति का

### इंदौर संकेत प्रतिनिधि

**इंदौर** • मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया को लेकर आयोग की सचिव बबिता मरकाम ने ही पत्र लिख दिया है। संचालनालय मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लैटरपेड पर यह पत्र प्रताप करोसिया को ही लिखा गया है। इसमें साल 2008 के नियमों का हवाला देकर मरकाम ने लिखा कि आपकी नियुक्ति 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। नियम के तहत तीन साल या शासन द्वारा मनोनयन वापस लेने तक यह वैध रहती है। यह समय पूरा हो गया है इसलिए राज्य शासन के नियमानुसार आपको दी गई सभी सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं।

करोसिया ने इस पत्र के आने के बाद इसे नियमविरुद्ध बताते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के साथ ही आयुक्त नगरीय प्रशासन व बबिता मरकाम को भी पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने मरकाम को इस चिट्ठी पर स्टे दे दिया है।



साथ ही सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। करोसिया ने इस संबंध में सीएम मोहन यादव को भी पत्र लिखा है और मामले की जानकारी दी है। इसमें उनकी नियुक्ति के पत्र का भी हवाला दिया गया है। शासन द्वारा जारी 15 अप्रैल 2023 के नियुक्ति पत्र में साफ लिखा है कि करोसिया की नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक रहेगी। यह नियुक्ति शासन की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा होती है। वहीं कैबिनेट

## एमवाय अस्पताल में सिस्टम फेल, बाहर कराना पड़ रही जांघें

# सीटी स्कैन और एमआरआई सब ताले में बरकरार, नतीजा मरीजों पर हजारों की मार

### इंदौर संकेत प्रतिनिधि

**इंदौर** • एमवायएच, जहां प्रदेशभर से गरीब मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। वहीं अब तैयार सुविधाओं पर ताले एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई अत्याधुनिक यूनिट्स मरीजों से धूल खा रही हैं और मरीजों को मजबूरन निजी जांच केंद्रों में जेब ढीली करनी पड़ रही है। एमवायएच अत्याधुनिक सीटी-स्कैन, एमआरआई सेंटर पूरी तरह बनकर तैयार हैं, लेकिन संचालन शुरू नहीं होने से मरीजों को निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त या कम खर्च में मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध न होने से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों पर दोहरी मार पड़ रही है।

मरीजों को करना पड़ा रहा लंबा इंतजार: इसी प्रकार अस्पताल की प्रथम मंजिल पर बना आधुनिक ऑपरेशन थिएटर (ओटी) कॉम्प्लेक्स भी लंबे समय से तैयार है, लेकिन टेकेदार और अस्पताल प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद के कारण इसका उपयोग शुरू नहीं हो पाया है। इसके चलते सर्जरी की क्षमता बढ़ने के बजाय सीमित ही बनी हुई है और कई मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गंभीर मामलों में देरी मरीजों की सेहत पर भी असर डाल



सकती है, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। वहीं, अस्पताल के तल मंजिल पर बनाए गए एन अकाउंट विभाग में भी सीपेज (सीलन) की समस्या बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। रिनोवेशन के बाद भी यह विभाग अब तक शिफ्ट नहीं हो सका है, जिसके कारण बिलिंग, रिकॉर्ड प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ रहा है और व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उनका उपयोग शुरू न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ओर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार बजट बढ़ा रही है और नई सुविधाओं का विस्तार कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर तैयार संसाधनों का उपयोग न होना व्यवस्था की कार्यशीली पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

# एचएसआरपी प्लेट नहीं तो बंद होगा पीयूसी, आरटीओ सख्त

### इंदौर संकेत प्रतिनिधि

**इंदौर** • हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट, एचएसआरपी, नहीं होने पर प्रदूषण प्रमाण पत्र, पीयूसी, बनवाना संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश के करीब 63 लाख और इंदौर के 80 हजार से ज्यादा वाहन सीधे प्रभावित होंगे। दरअसल, विभाग की खास नजर अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर है, जिनमें अभी तक एचएसआरपी नहीं लगाई गई है। नए नियम के लागू होते ही ऐसे वाहन मालिकों को सबसे पहले नंबर प्लेट अपडेट करवाना होगा तभी वे पीयूसी बनवा सकेंगे। बिना पीयूसी के सड़क पर वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और चालान बनेंगे। यह काम भी अटकेंगे एचएसआरपी नहीं होने का असर सिर्फ पीयूसी तक सीमित नहीं रहेगा। वाहन ट्रांसफर, फिटनेस, रिन्यूअल जैसे आरटीओ से जुड़े जरूरी काम भी अटक सकते हैं।

**क्यों जरूरी है एचएसआरपी-**अधिकारियों के मुताबिक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट सिर्फ औपचारिकता नहीं,



बल्कि सुरक्षा का अहम हिस्सा है। इसमें खास कोडिंग और सुरक्षा फीचर्स होते हैं जो वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल को रोकने में मदद करते हैं। सरकार पहले भी कई बार इसकी समय-समया बढ़ा चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब तक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। परिवहन विभाग साफ संकेत दे चुका है कि अब नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यही बेहतर है कि वे समय रहते अपनी गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाकर आने वाली परेशानियों से बचें।

# बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने दी पुलिस विभाग को खुलेआम चुनौती, खुलकर उतरे बेटे के पक्ष में

### इंदौर संकेत प्रतिनिधि

**इंदौर** • मध्यप्रदेशके शिवपुरी में इन दिनों सियासी पारा सातवें आसमान पर है। मामला एक सड़क हादसे से शुरू हुआ था। वहीं अब सीधे तौर पर सत्ता बनाम खाकी की जंग में तब्दील हो गया है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी, जिन्होंने कुछ दिन पहले नैतिकता की दुहाई दी थी, अब पुलिस अधिकारियों को सरेआम औकात याद दिलाने पर उतर आए हैं।

**बदले-बदले से हैं विधायक के तेवर-**मामले की शुरुआत 16 अप्रैल को करेरा में हुए एक हादसे से हुई थी। उस वक्त विधायक प्रीतम लोधी के सुर काफी नरम थे। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर दावा किया था कि उनके लिए परिवार नहीं, बल्कि जनता सर्वोपरि है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील भी की थी। वहीं, जैसे-जैसे जांच की आंच उनके करीब पहुंची, विधायक



की भाषा में न्याय की जगह धमकी ने ले ली। विधायक की नाराजगी को सीधा निशाना बने हैं एसडीओपी आईपीएस आयुष जाखड़। लोधी ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि एसडीओपी कहता है कि यहां दिख मत जाना। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या करेरा तरे डैडी का है? मेरा बेटा करेरा आया भी और चुनाव भी

## जातें करेरा सड़क हादसे में क्या हुआ था?

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश ने अपनी कार से सड़क पर चल रहे पांच लोगों को टक्कर मार दी थी। यह घटना इतनी गंभीर थी कि पांच लोगों की जान खतरे में पड़ गई। घायलों को तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया था। पुलिस ने पहले वाहन जब्त किया था। दो दिन पहले दिनेश ने कार में जुर्माना भरा और गाड़ी छुड़वा ली। उसके बाद उसे एसडीओपी ने फिर से थाने बुलाया था।

लड़ेगा, तरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करते हुए अपना इतिहास तक देखने की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा

कि यदि पुलिस ने दबाव बनाने या पक्षपात करने की कोशिश की, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका कारनामा जवाब देंगे। विधायक का आरोप है कि इस मामले को कांग्रेस की तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। **विवादों से पुराना नाता है लोधी परिवार का-**यह पहली बार नहीं है जब प्रीतम लोधी या उनका परिवार विवादों के घेरे में आया है। विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर 2023 में धमकी देने और 2024 में ग्वालियर में पड़ोसियों पर गाड़ी चढ़ाने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। खुद विधायक प्रीतम लोधी का रिकॉर्ड भी साफ नहीं रहा है; उन पर दंगा, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं। 2022 में तो उन्हें एक विवादित बयान के कारण पार्टी से निष्कासित भी किया गया था, हालांकि चुनाव से ठीक पहले उनकी वापसी हुई थी।

# गुजरात लाइन बंद, झाबुआ-आलीराजपुर की शराब दुकान में घाटा, इंदौर से 432 करोड़ की आय अधिक

### इंदौर संकेत प्रतिनिधि

**इंदौर** • शराब टेकेदारों की आपसी लड़ाई और शासन की सख्ती के चलते गुजरात में जाने वाली अवैध शराब सप्लाई टप हो गई है। इसके चलते इस सप्लाई से जुड़े गुजरात बांडर के अहम जिले आलीराजपुर और झाबुआ की दुकानों में सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। उधर इंदौर जिले ने इसकी जमकर भरपाई की है और प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व दिया है। मध्य प्रदेश में आखिरकार सभी 3 हजार 553 शराब दुकान बिक गई हैं। अब इन्हें चलाने के लिए निगम, मंडल बनाने की जरूरत नहीं होगी। इससे सरकार को 18 हजार 679 करोड़ की आय हुई है। यह वित्तीय साल 2025-26 के ठेके (16 हजार 627) से 12.34 फीसदी यानी 2050 करोड़ अधिक है। इस अतिरिक्त 2 हजार 50 करोड़ की

आय में इंदौर जिले का सर्वाधिक हिस्सा 432 करोड़ (21 फीसदी) है। कुल मिलाकर इंदौर जिले ने एमपी की आबकारी नीति को बहुत बड़ा सहारा दिया और घाटा होने से बचा लिया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आलीराजपुर का शराब टेका बीते साल 117 करोड़ में गया था। इस बार लक्ष्य 141 करोड़ रुपए था, लेकिन केवल 94 करोड़ रुपए में ही यह ठेके गए। बीते साल से भी 20 फीसदी राजस्व कम हो गया, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक घाटा है। वहीं झाबुआ में 287 करोड़ में ठेके गए थे और इस बार 345 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन ठेके केवल 243 करोड़ में गए। यहां भी 15 फीसदी घाटा हुआ है। इसके साथ ही मंडसौर, जबलपुर, आगर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, रतलाम, नीमच जिले भी बीते साल के ठेके से कम भाव पर गए हैं। इससे सरकार को



बड़ा झटका लगा है।

वहीं बीते साल के ठेकों से सर्वाधिक आय छोटे जिलों में दिखाई है। सबसे ज्यादा 61 फीसदी की बढ़ोतरी मैहर जिले में हुई। यहां पर ठेके बीते साल 80 करोड़ में गए थे, जो इस बार 130 करोड़ में गए हैं। इसी तरह मंडला में 97 करोड़ में जो ठेके बीते साल गए थे, वह इस बार 52

फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 148 करोड़ में गए। इसी तरह सीधी में 124 करोड़ के ठेके इस बार 186 करोड़ में गए और बीते साल से 50 फीसदी अधिक बढ़ोतरी हुई। बीते साल से अधिक आय में प्रतिशत में भी गए थे, जो इस बार 130 करोड़ में गए हैं। लेकिन राशि की बात की जाए तो इंदौर ने ही खजाना भरा है। दुकान को

## झाबुआ, आलीराजपुर से गुजरात लाइन बंद

मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से नौ जिले ऐसे रहे हैं जिसमें बीते साल से भी कम राजस्व आया और सरकार को तगड़ा झटका लगा। चौकाने वाली बात रही है कि आलीराजपुर और झाबुआ में ही यह सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। यह जिले गुजरात से लगे होने के चलते सबसे पहले सिंगल टेके में जाते थे। इसकी वजह है कि बीते एक साल से इन जिलों से गुजरात में जाने वाली अवैध शराब की सप्लाई टप हो गई है। टेकेदारों में आपस में कॉम्पिटिशन होने से एक-दूसरे को निपटाने का खेल चला, जिससे कई गाड़ियां पकड़ी गईं। उधर मोहन यादव की सरकार ने जमकर सख्ती की इससे भी यह लाइन टप हो गई।

लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और एसी आबकारी अभिषेक तिवारी की नई युधिष्ठिर नीति सफल हुई। इंदौर का साल 2025-26 का टेका 1752 करोड़ में गया था, जो इस बार 2 हजार 184 करोड़ में गया है। यह 432 करोड़ यानी करीब 25 फीसदी अधिक है। इस बार लक्ष्य 2 हजार 102 करोड़ था, जहां अन्य जिलों को छोटे लक्ष्य भी पार करने में पसीना

आ गया, वहां इसे भी इंदौर पार कर गया है। इंदौर ने सर्वाधिक 2 हजार 184 करोड़ रुपए दिए। वहीं इसके बाद भोपाल ने एक हजार 206 करोड़ की आय शराब ठेकों से दी है। जबलपुर ने 910 करोड़ दिए। ग्वालियर ने 684 करोड़ दिए। उज्जैन से 605 करोड़ की आय हुई है। धार और सागर से 601-601 करोड़ की आय हुई है।